खंड १ नंबर ३ जुलाई २०१७

आरआईएस डायरी

–अंतरराष्ट्रीय विकास के लिए नीतिगत अनुसंधान

भारत–आसियान संबंध–एक्ट ईस्ट नीति का आधार

माननीया श्रीमती सुषमा स्वराज, विदेश मंत्री, भारत सरकार, आसियान–भारत साझेदारी पर मुख्य भाषण देती हुईं। (बाएं से दाएं); प्रो. सचिन चतुर्वेदी, महानिदेशक, आरआईएस, श्री हरदीप एस पुरी, अध्यक्ष, आरआईएस, माननीय श्री तोन सिंह थान, भारत में वियतनाम के राजदूत, श्री अमर सिन्हा, सचिव (आर्थिक संबंध), विदेश मंत्रालय और डॉ. प्रबीर डे, समन्वयक, आरआईएस स्थित एआईसी।

आसियान–भारत साझेदारी के 25 साल पूरे होने के अवसर पर आरआईएस और आरआईएस स्थित आसियान इंडिया सेंटर (एआईसी) ने भारत सरकार की माननीया विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज को 22 जून 2017 को नई दिल्ली में 'आसियान–भारत साझेदारी' पर मुख्य संबोधन के लिए आमंत्रित किया। इस अवसर पर आरआईएस के महानिदेशक प्रो. सचिन चतुर्वेदी ने स्वागत भाषण और आरआईएस के अध्यक्ष श्री हरदीप एस पुरी ने आरंभिक भाषण दिया। अपने मुख्य भाषण के दौरान श्रीमती सुषमा स्वराज ने आसियान के साथ भारत की रणनीतिक साझेदारी के कई पहलुओं पर चर्चा की। भारत एशिया–प्रशांत क्षेत्र में उपयुक्त क्षेत्रीय सुरक्षा व्यवस्था विकसित करने की दिशा में आसियान के साथ मिलकर काम कर रहा

पृष्ठ 4 पर जारी.....

प्रधानमंत्री द्वारा 'एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर' विज़न दस्तावेज की सराहना

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 23 मई 2017 को अहमदाबाद में अफ्रीकी विकास बैंक (एएफडीबी) की वार्षिक बैठक के उद्घाटन अवसर पर अपने संबोधन में रेखांकित करते हुए कहा था, 'मैं टोक्यो यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री अबे के साथ अपनी विस्तृत बातचीत को सहर्ष स्मरण कर रहा हूं। हमने सभी के लिए विकास संभावनाएं बढ़ाने से जुड़ी अपनी प्रतिबद्धताओं पर चर्चा की। अपने संयुक्त घोषणा पत्र में हमने एक एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर (एएजीसी) का उल्लेख किया और अफ्रीका के अपने भाइयों एवं बहनों

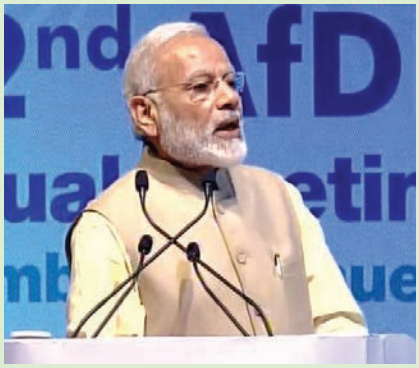

माननीय प्रधानमंत्री अफ्रीकी विकास बैंक (एएफडीबी) की वार्षिक बैठक में भाषण देते हुए।

के साथ आगे बातचीत करने का प्रस्ताव रखा। इस संदर्भ में भारत और जापान के अनुसंधान संस्थानों ने एक विज़न दस्तावेज पेश किया है। मैं आरआईएस, ईआरआईए और आईडीई–जेट्रो को इसे संजोने में उनके किये गये प्रयासों के लिए बधाई देता हूं। अफ्रीका के थिंक–टैंक्स के साथ सलाह–मशविरा करके ही यह काम बखूबी पूरा किया गया था। मेरा यह मानना है कि विज़न दस्तावेज को बाद में बोर्ड की बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा। इसके पीछे अभिप्राय यह है कि भारत और जापान

पृष्ठ 6 पर जारी.....

अन्य सतत लक्ष्यों में सफलता के लिए लक्ष्य 5 अहम

माननीया कपड़ा मंत्री श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी मुख्य भाषण देती हुईं। (बाएं से दाएं); डॉ. अशोक कुमार जैन, श्री अरविंद पनगढिया, श्री हरदीप एस पुरी और प्रो. सचिन चतुर्वेदी।

आरआईएस ने नीति आयोग और संयुक्त राष्ट्र के साथ मिलकर विशिष्ट एसडीजी लक्ष्यों पर केंद्रित करते हुए कई राज्यों के साथ 'राष्ट्रीय मंत्रणा' का आयोजन किया। इस श्रृंखला के तहत नई दिल्ली में 11 अप्रैल 2017 को महिला–पुरुष समानता के मुद्दों से संबंधित 'एसडीजी 5' पर और 13 अप्रैल 2017 को 'शून्य भूख' से संबंधित 'एसडीजी 2' पर दो राष्ट्रीय मंत्रणाओं का आयोजन किया गया। महिला–पुरुष समानता पर मंत्रणा का शुभारंभ डॉ. अशोक कुमार जैन, सलाहकार (ग्रामीण विकास और एसडीजी), नीति आयोग के स्वागत भाषण से हुआ। श्री हरदीप एस पुरी, अध्यक्ष, आरआईएस, ने विशेष भाषण दिया और नीति आयोग के उपाध्यक्ष श्री अरविंद पनगढिया ने उद्घाटन भाषण दिया। इस अवसर पर कपड़ा मंत्री श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी ने मुख्य भाषण दिया। प्रो. सचिन चतुर्वेदी, महानिदेशक, आरआईएस, ने भी प्रतिभागियों को संबोधित किया।

माननीया मंत्री ने विशेष जोर देते हुए कहा कि 'एसडीजी 5' अत्यंत कुशलता के साथ विभिन्न लक्ष्यों की प्राप्ति से जुड़ जाएगा। उन्होंने शिक्षा की भूमिका पर विशेष बल दिया, जो न केवल सांसद या पंचायत स्तर पर, बल्कि निचले स्तर पर भी निर्णय लेने की क्षमता के मामले में पुरुषों और महिलाओं के बीच समानता लाने में बड़ी सहायक होगी। इसके साथ ही यह पुरुष एवं महिला के पारिश्रमिक में अंतर को कम करने में भी अहम भूमिका निभाने जा रही है। उन्होंने महिला–पुरुष समानता को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजनाओं जैसे बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, मुद्रा योजना और उज्ज्वला योजना के साथ–साथ सभी स्कूलों में लड़कियों के लिए शौचालय बनवाए जाने का भी उल्लेख किया।

नीति आयोग के उपाध्यक्ष श्री अरविंद पनगढिया ने कहा कि अंततः हम सभी लिंग, जाति या धर्म की परवाह किए बिना सभी मनुष्यों की समानता में विश्वास करते हैं, अतः निःसंदेह 'एसडीजी 5' को सर्वथा केंद्रीय लक्ष्य होना चाहिए। आरआईएस के अध्यक्ष श्री हरदीप एस पुरी ने मुख्य रूप से छह सतत विकास लक्ष्यों और कार्यान्वयन के साधनों पर ध्यान केंद्रित किया जिनमें महिला–पुरुष समानता और महिला सशक्तिकरण (जीईडब्लूई) के तीन प्रमुख पहलु शामिल हैं: शारीरिक सुरक्षा, ईमानदारी एवं गरिमा, सुरक्षा और सम्मान, मानव अधिकार, समान क्षमताएं, अवसर एवं विकल्प, संपूर्ण सशक्तिकरण, राय जाहिर करने में समान भागीदारी एवं निर्णय लेने में नेतृत्व, समानता भागीदारी नेतृत्व पर चर्चा की।

'खाद्य सुरक्षा हासिल करने, बेहतर पोषण और सतत कृषि को बढ़ावा देने' विषय को लेकर 'एसडीजी 2' पर आयोजित 13 अप्रैल 2017 को दूसरी राष्ट्रीय मंत्रणा में डॉ. अशोक कुमार जैन, सलाहकार (ग्रामीण विकास एवं एसडीजी), नीति आयोग ने स्वागत भाषण दिया। श्री हरदीप एस पुरी, अध्यक्ष, आरआईएस, और श्री यूरी अफानसीव, संयुक्त राष्ट्र के निवासी समन्वयक, भारत ने उद्घाटन सत्र के दौरान विशेष भाषण दिए। मुख्य भाषण श्री वाई. एस. माथुर, अपर सचिव, नीति आयोग द्वारा दिया गया।

डॉ.बिबेक देबरॉय, सदस्य, नीति आयोग, ने 'खाद्य और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने' पर सत्र–1 की अध्यक्षता की। सत्र के दौरान पैनल के सदस्यों (पैनलिस्ट) में श्री आमोद कंठ, संस्थापक, प्रयास, श्री दीपक कुमार, संयुक्त सचिव, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, डॉ. ए. लक्ष्मैया, वैज्ञानिक, राष्ट्रीय पोषण संस्थान, डॉ. शिवेंद्र श्रीवास्तव, वैज्ञानिक, राष्ट्रीय कृषि अर्थशास्त्र

पृष्ठ 10 पर जारी.....

विदेश व्यापार नीति (2015–2020) की मध्यावधि समीक्षा

वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) माननीया श्रीमती निर्मला सीतारमण सत्र की अध्यक्षता करती हुईं। (बाएं से दाएं); प्रो. सचिन चतुर्वेदी, सुश्री रीता तेवतिया, वाणिज्य सचिव, श्री हरदीप एस पुरी और श्री ए.के. भल्ला।

भारत चूंकि जीएसटी को लागू करने की प्रक्रिया से गुजर रहा है इसका भारत की व्यापार नीति पर क्या संभावित असर हो सकता है इसके विश्लेषण के लिये आरआईएस ने भारत सरकार के वाणिज्य विभाग के सहयोग से 6 मई 2017 को नई दिल्ली में विदेश व्यापार नीति (2015–2020) की मध्यावधि समीक्षा का आयोजन किया। भारत सरकार की वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) माननीया श्रीमती निर्मला सीतारमण ने बैठक की अध्यक्षता की। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रो. सचिन चतुर्वेदी, महानिदेशक, आरआईएस के स्वागत भाषण के साथ हुआ। इस अवसर पर वाणिज्य सचिव सुश्री रीता तेवतिया ने आरंभिक भाषण दिया और आरआईएस के अध्यक्ष श्री हरदीप एस पुरी ने भी प्रतिभागियों को संबोधित किया। विदेश व्यापार महानिदेशक (डीजीएफटी) श्री ए.के. भल्ला और आरआईएस के प्रो. एस. के. मोहंती ने इस अवसर पर प्रस्तुतियां दीं। इसके बाद प्रतिभागियों ने विभिन्न मुद्दों पर विचार–विमर्श किया। दूसरे सत्र के आयोजन का उद्देश्य अन्य एशियाई अर्थव्यवस्थाओं में किए गए निर्यात संवर्धन उपायों पर चर्चा करना था। विदेश व्यापार के अतिरिक्त महानिदेशक श्री निकुंज कुमार श्रीवास्तव ने समापन भाषण दिया।

आसियान–भारत साझेदारी की 25वीं वर्ष गाँठ

आरआईएस एवं आरआईएस स्थित आसियान इंडिया सेंटर (एआईसी) ने 'आसियान–भारत साझेदारी के 25 वर्ष' पूरे होने के अवसर पर 22 जून 2017 को संयुक्त रूप से नई दिल्ली में चर्चा का आयोजन किया।

कार्यक्रम का शुभारंभ प्रो. सचिन चतुर्वेदी, महानिदेशक, आरआईएस के स्वागत भाषण के साथ हुआ। आरआईएस के अध्यक्ष श्री हरदीप एस पुरी ने सत्र की अध्यक्षता की। राजदूत अमर सिन्हा, सचिव (आर्थिक संबंध), विदेश मंत्रालय, भारत सरकार ने विशेष भाषण दिया। मुख्य प्रतिभागियों में आसियान के सदस्य देशों के राजदूत, भारतीय राजनयिक, शिक्षाविद और शोधकर्ता शामिल थे।

आरआईएस स्थित आसियान–भारत केंद्र के समन्वयक डॉ. प्रबीर डे ने आसियान–भारत संबंधों के 25 साल पूरे होने पर अपनी विस्तृत प्रस्तुति में, निवेश, कनेक्टिविटी और सांस्कृतिक संबंधों की प्रमुखता का उल्लेख किया। आसियान मिशन प्रमुखों ने भी अपने–अपने विचार प्रस्तुत किये।

आसियान–भारत साझेदारी के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित गोलमेज परिचर्चा प्रगति पर।

सतत आर्थिक विकास के लिए विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार सृजन

दक्षिण एशिया में सतत आर्थिक विकास के लिए एक रणनीति के रूप में विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार सृजन पर सम्मेलन के विभिन्न प्रतिभागी।

आरआईएस ने एसएसीईपीएस अनुसंधान कार्यक्रम के एक भाग के रूप में एशिया फाउंडेशन के सहयोग से 'दक्षिण एशिया में सतत आर्थिक विकास के लिए एक रणनीति के रूप में विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार सृजन' पर 2016–17 में एक प्रमुख अनुसंधान परियोजना शुरू की है। विनिर्माण क्षेत्र, मौजूदा असमानताओं को समाप्त करते हुए लाभप्रद, उत्पादक एवं व्यापक रोजगार सृजन के जरिए, दक्षिण एशिया में सतत आर्थिक विकास सुनिश्चित करने की कुंजी है। इस परियोजना के तहत पहली कार्यशाला नई दिल्ली में 5 दिसंबर 2016 को आयोजित की गई थी जिसमें दक्षिण एशियाई देशों के विशेषज्ञ प्रतिभागियों ने भाग लिया था।

इस दिशा में आगे कदम बढ़ाते हुए तीनों सस्थानों के सहयोग से 21 जून 2017 को 'दक्षिण एशिया में सतत आर्थिक विकास के लिए विनिर्माण क्षेत्र की रणनीति के तहत रोजगार सृजन' पर दूसरी एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ प्रो. सचिन चतुर्वेदी, महानिदेशक, आरआईएस, और कार्यकारी निदेशक, एसएसीईपीएस के स्वागत भाषण के साथ हुआ। डॉ. सागर परसाई, देश प्रतिनिधि, एशिया फाउंडेशन और प्रो. दीपक नैय्यर, अर्थशास्त्र के ससम्मान सेवामुक्त (एमेरिटस) प्रोफेसर, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली, ने आरंभिक भाषण दिए। विभिन्न सत्रों में विनिर्माण क्षेत्र एवं रोजगार सृजन, औद्योगिक नीति, बाह्य क्षेत्र एवं रोजगार और कौशल, प्रतिस्पर्धी क्षमता एवं स्थायित्व से संबंधित मुद्दों पर चर्चा हुई। विस्तृत एजेंडा आरआईएस की वेबसाइट www.ris.org.in पर उपलब्ध है।

आसियान के साथ रिश्ता...
पृष्ठ 1 से जारी

है, जो विवादों के शांतिपूर्ण हल, उभरती एवं गैर–पारंपरिक चुनौतियों का सहयोगात्मक समाधान ढूंढने और आसियान की केंद्रीयता के लिए आवश्यक समर्थन पर टिका हुआ है। उन्होंने यह बात दोहराई कि भारत क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी से जुड़ी वार्ताओं में सक्रियता के साथ भाग ले रहा है जिनमें आसियान और उसके छह एफटीए भागीदार शामिल हैं। इसे जब भी अंतिम रूप दिया जाएगा तो वह सबसे बड़ी क्षेत्रीय व्यापार व्यवस्था होगी और उसकी हिस्सेदारी विश्व व्यापार में लगभग 40 प्रतिशत होगी। मंत्री महोदया ने कहा कि भूमि, वायु और समुद्री मार्गों से कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि कनेक्टिविटी के गलियारों को आर्थिक सहयोग के गलियारों में परिवर्तित किया जा सके।

भारत की 'एक्ट ईस्ट नीति' में पूर्वोत्तर क्षेत्र एक 'स्वाभाविक साझेदार' है। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए विशिष्ट प्रस्ताव पेश किए गए हैं, जिनमें उच्च क्षमता वाले एक क्षेत्रीय फाइबर–ऑप्टिक नेटवर्क की स्थापना करना भी शामिल है और जिसमें राष्ट्रीय ग्रामीण ब्रॉडबैंड नेटवर्क एवं दूरदराज के क्षेत्रों में अवस्थित डिजिटल गांव पूरक व्यवस्था के तौर पर काम करेंगे। व्याख्यान कार्यक्रम के आखिर में एआईसी के समन्वयक डॉ.प्रबीर डे ने धन्यवाद ज्ञापन किया।

ब्रिक्स देशों के बीच वित्तीय सहयोग

7 अप्रैल 2017 को 'ब्रिक्स देशों के बीच वित्तीय सहयोग; मौजूदा व्यवस्थाएं और भावी संवाद' विषय पर आरआईएस मे ब्रेकफास्ट सेमिनार का आयोजन किया गया। डॉ. प्रियदर्शी दास, रिसर्च एसोसिएट, आरआईएस, ने इस विषय पर एक प्रस्तुति दी। श्री आलोक डिमरी, संयुक्त सचिव (एमईआर), विदेश मंत्रालय, भारत सरकार, ने इस परिसवांद की अध्यक्षता की।

भारत–रूस साझेदारीः नई संभावनाएं

गोलमेज सम्मेलन में प्रो. सचिन चतुर्वेदी, माननीय अनातोली वी. कार्गापोलोव, प्रभारी उपराजदूत, रूसी संघ का दूतावास, श्री हरदीप एस. पुरी, राजदूत पी. एस. राघवन, श्री यूरी अफानासीव और डॉ. राम उपेंद्र दास (बाएं से दाएं)।

'भारत–रूस राजनयिक संबंधों के 70 साल पूरे होने' के अवसर पर आयोजित विभिन्न स्मरणीय कार्यक्रमों को ध्यान में रखते हुए आरआईएस द्वारा 6 अप्रैल 2017 को नई दिल्ली में 'भारत–रूस साझेदारी को मजबूत करनेः नई संभावनाएं तलाशने पर एक सम्मेलन आयोजित किया गया। इस आयोजन में वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों, नीति निर्माताओं, शिक्षाविदों और व्यापार, कारोबार एवं मीडिया जगत के प्रतिनिधियों ने परिचर्चा में भाग लिया।

सम्मेलन का शुभारंभ आरआईएस के महानिदेशक प्रो.सचिन चतुर्वेदी के स्वागत भाषण और आरआईएस के अध्यक्ष श्री हरदीप एस. पुरी के आरंभिक भाषण के साथ हुआ। राजदूत पी. एस. राघवन, रूसी संघ में भारत के पूर्व राजदूत ने उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता की। माननीय श्री अनातोली वी. कार्गापोलोव, प्रभारी उपराजदूत, रूसी संघ का दूतावास, नई दिल्ली, और श्री यूरी अफानासीव, भारत में संयुक्त राष्ट्र के निवासी समन्वयक एवं यूएनडीपी के निवासी प्रतिनिधि, नई दिल्ली, ने विशेष भाषण दिए। डॉ. राम उपेंद्र दास, प्रोफेसर, आरआईएस ने समापन भाषण दिया।

राजदूत अशोक सज्जनहार, कजाखस्तान में भारत के पूर्व राजदूत, ने व्यापार, निवेश और विकास सहयोग पर आयोजित पहले सत्र की अध्यक्षता की। प्रो. गुलशन सचदेवा, प्रोफेसर, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली, श्री प्रणव कुमार, प्रमुख (व्यापार एवं अंतर्राष्ट्रीय नीति), भारतीय उद्योग परिसंघ, नई दिल्ली, श्री धरमवीर, उद्योगपति, भारत–रूस व्यापार और वाइस एडमिरल अनूप सिंह (सेवानिवृत्त), पूर्व कमांडर–इन–चीफ, पूर्वी नौसेना कमान, भारत सरकार, इस अवसर पर मुख्य वक्ताओं में थे।

'आगे के मार्ग' पर दूसरे सत्र की अध्यक्षता डॉ. एस. आर. हाशिम, अध्यक्ष, मानव विकास संस्थान, नई दिल्ली ने की। इस सत्र में मुख्य वक्ताओं में प्रो. अनुराधा एम. चेनॉय, प्रोफेसर, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, सुश्री ज्योति मल्होत्रा, वरिष्ठ पत्रकार एवं अध्यक्ष, साउथ एशियन वूमन इन मीडिया (एसएडब्ल्यूएम), प्रो. संजय पांडे, प्रोफेसर, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली, और डॉ. ऐश नारायण राय, निदेशक, सामाजिक विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली, शामिल थे। सम्मेलन के अंत में श्री जी.वी. श्रीनिवास, संयुक्त सचिव (ईआरएस), विदेश मंत्रालय, भारत सरकार ने समापन भाषण दिया।

सतत विकास और आर्थिक समृद्धि हेतु नीली अर्थव्यवस्था की रूपरेखा

आरआईएस ने पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के साथ संयुक्त रूप से 25 अप्रैल 2017 को नई दिल्ली में 'सतत विकास और आर्थिक समृद्धि के लिए नीली अर्थव्यवस्था की रूपरेखा' पर एक सार्वजनिक व्याख्यान का आयोजन किया। इस अवसर पर प्रो. चार्ल्स कोलगन, राष्ट्रीय महासागर अर्थशास्त्र कार्यक्रम (एनओईपी), संयुक्त राज्य अमेरिका, ने विशेष व्याख्यान दिया। प्रो. चार्ल्स कोलगन, सागर से जुड़ी, अर्थव्यवस्थाओं, परिवहन एवं आर्थिक विकास, शहरी नियोजन और नीतिगत विश्लेषण के एक प्रख्यात विद्वान हैं।

प्रो. चार्ल्स कोलगन, राष्ट्रीय महासागर अर्थशास्त्र कार्यक्रम (एनओईपी), संयुक्त राज्य अमेरिका 'सतत विकास और आर्थिक समृद्धि के लिए नीली अर्थव्यवस्था की रूपरेखा' पर सार्वजनिक व्याख्यान देते हुए।

हाल के वर्षों में, तटीय अर्थव्यवस्थाओं के लिए नीली अर्थव्यवस्था (ब्लू इकोनॉमी), एक प्रमुख विकास प्रतिमान के रूप में उभर कर सामने आई है। सागर क्षेत्र तटीय देशों के लिए आर्थिक विकास का एक प्रमुख केन्द्र है और सागर की अच्छा रखरखाव सुनिश्चित करना समुद्री संसाधनों के सतत उपयोग की दृष्टि से सबसे अहम आवश्यकता है। इस संबंध में, 'एसडीजी 14' उच्च आर्थिक विकास दर हासिल करने के मामले में तटीय अर्थव्यवस्थाओं में नीली अर्थव्यवस्था के अत्यंत प्रभावकारी साबित होने में निश्चित रूप से पूरक होगा। इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए घरेलू, क्षेत्रीय और वैश्विक महासागर नीतियों को एकीकृत करने की जरूरत है, ताकि नीली अर्थव्यवस्था से जुड़ी नीतियों की प्रभावशीलता को सही स्वरूप प्रदान किया जा सके।

कार्यक्रम का शुभारंभ प्रो. सचिन चतुर्वेदी, महानिदेशक, आरआईएस के स्वागत भाषण के साथ हुआ। श्री हरदीप एस पुरी, अध्यक्ष, आरआईएस ने सत्र की अध्यक्षता की। आरआईएस के प्रोफेसर डॉ. एस.के. मोहंती ने आरआईएस के 'ब्लू इकोनॉमी प्रोग्राम' के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्रदान की। राजदूत के.वी. भगीरथ, महासचिव, आईओआरए, ने विशेष भाषण दिया। व्याख्यान के बाद खुली परिचर्चा भी हुई।

प्रधानमंत्री ने 'एशिया अफ्रीका ग्रोथ कारिडोर'...
पृष्ठ 1 से जारी

अन्य इच्छुक भागीदारों के साथ मिलकर कौशल, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे, विनिर्माण एवं कनेक्टिविटी में संयुक्त पहल करने की संभावनाओं को तलाशेंगे।'

'एएजीसी' का विचार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री शिंजो अबे द्वारा नवंबर 2016 में जापान में जारी संयुक्त घोषणा पत्र में उभर कर सामने आया था। एएजीसी के तहत आम लोगों पर केंद्रित सतत विकास रणनीति की परिकल्पना की जाएगी जिसका विवरण समस्त एशिया एवं अफ्रीका में विस्तृत परामर्श प्रक्रिया के जरिए विकसित किया जाएगा और जिसमें विभिन्न हितधारकों को शामिल किया जाएगा।

'एएजीसी' को विकास एवं सहयोग परियोजनाओं, गुणवत्तापूर्ण बुनियादी ढांचे एवं संस्थागत कनेक्टिविटी, क्षमता एवं कौशल वृद्धि और लोगों के बीच साझेदारी के चार खंभों पर स्थापित किया जाएगा। लोगों के बीच साझेदारी की केन्द्रीयता इस पहल की अनूठी विशेषता होगी। 'एएजीसी' की ताकत को अफ्रीका के विभिन्न देशों और उप–क्षेत्रों की विकास प्राथमिकताओं के साथ जोड़ा जाएगा, जिसके लिए उनके बीच एक साथ मौजूद एकरूपता और विविधता से लाभ उठाया जाएगा। यह एक स्वतंत्र और खुले भारत–प्रशांत क्षेत्र के सपने को साकार करने हेतु एशिया एवं अफ्रीका के बीच और उनके भीतर विकास तथा पारस्परिक संपर्कों को बेहतर बनाने के लिए किया जाएगा।

'एएजीसी' के तहत स्वास्थ्य एवं औषधीय, कृषि एवं कृषि प्रसंस्करण, आपदा प्रबंधन और कौशल वृद्धि से जुड़ी विकास परियोजनाओं को भी प्राथमिकता दी जाएगी। एएजीसी के कनेक्टिविटी पहलुओं को गुणवत्तापूर्ण बुनियादी ढांचे से आवश्यक संबल मिलेगा। अफ्रीका और एशिया में एएजीसी की अगुवाई में विकास सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के लिए सामूहिक प्रतिबद्धता के प्रति अनुकूल होगा। एएजीसी विजन अध्ययन भारत, दक्षिण एशिया, दक्षिण–पूर्व एशिया, पूर्वी एशिया और ओशिनिया के साथ अपने एकीकरण के जरिए अफ्रीका के लिए आर्थिक लाभ सुनिश्चित करने हेतु भौगोलिक अनुकरण (सिमुलेशन)

मॉडल (जीएसएम) का उपयोग करेगा। एएजीसी कारोबारियों, लोगों एवं उन थिंक–टैंक्स को आपस में जोड़ने के लिए आवश्यक संस्थागत व्यवस्था और मॉडल विकसित करने में अहम योगदान देगा जो एशिया और अफ्रीका में एकीकरण के प्रयासों में प्रतिनिधित्व एवं योगदान करते हैं।

आरआईएस, जकार्ता स्थित आसियान एवं पूर्वी एशिया के लिए आर्थिक अनुसंधान संस्थान (ईआरआईए) और टोक्यो स्थित विकासशील अर्थव्यवस्था संस्थान (आईडीई–जेट्रो) ने एशियाई और अफ्रीकी थिंक–टैंक्स के साथ किए गए परामर्श के आधार पर विजन दस्तावेज विकसित किया है। यह दस्तावेज अहमदाबाद में एएफडीबी की वार्षिक बोर्ड बैठक के दौरान अलग से आयोजित किए गए एक कार्यक्रम में जारी किया गया था।

मेकांग–गंगा सहयोगः सुदृढ़ जुढ़ाव और मजबूत रिश्ते

आरआईएस, आरआईएस स्थित एआईसी और भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) के साथ साझेदारी में विदेश मंत्रालय ने 8 अप्रैल 2017 को नई दिल्ली में मेकांग–गंगा सहयोग (एमजीसी) पर एक नीतिगत संवाद का आयोजन किया जिसका शीर्षक था: 'सुदृढ़ जुढ़ाव और मजबूत रिश्ते'। इस अवसर पर प्रो. सचिन चतुर्वेदी, महानिदेशक, आरआईएस, ने स्वागत भाषण दिया और उद्घाटन भाषण, आरआईएस के अध्यक्ष श्री हरदीप एस पुरी ने दिया। सीआईआई प्रतिनिधित्व डॉ. दिनेश दुआ और भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (आईसीसीआर) के अध्यक्ष प्रो. लोकेश चंद्र ने विशेष भाषण दिए। सुश्री प्रीति सरन, सचिव (पूर्व), विदेश मंत्रालय ने मुख्य भाषण दिया और, साथ ही 'मेकांग–गंगा सहयोग; बाधाएं समाप्त करने और नए मुकाम की तलाश करने' पर एआईसी–आरआईएस रिपोर्ट भी जारी की। सुश्री पूजा कपूर, संयुक्त सचिव, विदेश मंत्रालय ने धन्यवाद ज्ञापन किया।

राजदूत प्रीति सरन, सचिव (पूर्व), विदेश मंत्रालय, भारत सरकार 'मेकांग–गंगा सहयोग; बाधाएं समाप्त करने और नए मुकाम की तलाश करने' पर एआईसी–आरआईएस रिपोर्ट जारी करती हुईं। (बाएं से दाएं) प्रो. सचिन चतुर्वेदी, सुश्री पूजा कपूर, संयुक्त सचिव, विदेश मंत्रालय, श्री हरदीप एस पुरी, प्रो लोकेश चंद्र, अध्यक्ष, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (आईसीसीआर) और डॉ.दिनेश दुआ, भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई)।

यह नीतिगत संवाद 24 जुलाई 2016 को विएनटिएन में आयोजित 7वीं मेकांग–गंगा सहयोग (एमजीसी) मंत्रिस्तरीय बैठक में माननीय विदेश राज्य मंत्री की घोषणा के मद्देनजर आयोजित किया गया था। उस बैठक के दौरान राज्य मंत्री ने घोषणा की थी कि भारत एमजीसी पर एक सेमिनार की मेजबानी करेगा जिस में आरआईएस स्थित एआईसी के साथ मजबूत कनेक्टिविटी बनाने और बहु–आयामी रिश्तों को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। एमजीसी के सदस्य देशों ने नीतिगत संवाद के लिए प्रतिभागियों को नामित किया था और विदेशी कार्यालयों के वरिष्ठ अधिकारियों सहित 100 से अधिक प्रतिनिधियों ने भी चर्चा में भाग लिया। नीतिगत संवाद को चार सत्रों में विभाजित किया गया, जिसका उद्देश्य कनेक्टिविटी के जरिए एमजीसी को मजबूत करने के लिए एक कार्रवाई योग्य नीतिगत एजेंडा तैयार करने में मदद करने हेतु नई पहलों एवं विचारों के संबंध में भारत और मेकांग देशों के अनुभवों से संबंधित विभिन्न विषयों पर गहन चर्चा को आसान बनाना था। इन सत्रों में प्रमुख विषय थेः भैतिक एवं डिजिटल कनेक्टिविटी, व्यापार, निवेश, वैल्यू चेन, सांस्कृतिक संबंध एवं जन संपर्क, आगे बढ़ना; विविधता का उपयोग करना, भविष्य का निर्माण करना।

डॉ. प्रबीर डे, समन्वयक, एआईसी, ने चर्चा का सार प्रस्तुत किया और धन्यवाद ज्ञापन किया।

चुलालांगकॉर्न विश्वविद्यालय का प्रतिनिधिमंडल

बैंकॉक स्थित चुलालांगकॉर्न विश्वविद्यालय (सीयू) के आसियान अध्ययन केन्द्र से चार सदस्यीय अनुसंधान टीम ने आरआईएस के संकाय के साथ परिचर्चा सत्र के लिए 16 मई 2017 को आरआईएस स्थित आसियान–भारत केंद्र का दौरा किया।

टीम के सदस्यों में डॉ. सूरत होराचायकुल, निदेशक, भारतीय अध्ययन केंद्र, राजनीति विज्ञान संकाय, डॉ. पीति सरसंगनम, सहायक प्रोफेसर, अर्थशास्त्र संकाय, डॉ. अनुपमा देवेन्द्रकुमार, शोधकर्ता, आसियान अध्ययन केंद्र, और श्री किटिपांग बूनकर्ड, ऑर्ट्स, चुलालांगकॉर्न विश्वविद्यालय, व्याख्याता (हिन्दी भाषा), संकाय बैंकॉक, थाईलैंड, शामिल हुए।

चुलालांगकॉर्न विश्वविद्यालय (सीयू), बैंकॉक के सदस्यगण, आरआईएस संकाय–सदस्यों के साथ।

उत्तरदायी अनुसंधान और नवाचार

विज्ञान और समाज के बीच उचित संतुलन स्थापित करने की जरूरत वर्तमान परिदृश्य में राष्ट्रीय एवं वैश्विक स्तरों पर और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है। आरआईएस इस मुद्दे पर काफी सक्रियता के साथ आवश्यक संवाद सुनिश्चित करता रहा है। आरआईएस ने इसके साथ ही विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार में पहुंच, बराबरी या निष्पक्षता (इक्विटी) और समावेशन (एईआई) के विचारों के आधार पर एक रूपरेखा विकसित की है जो वैश्विक स्तर पर उत्तरदायी अनुसंधान और नवाचार (आरआरआई) की नई अवधारणा के समान है। भारतीय संदर्भ में आरआरआई की प्रासंगिकता पर परिचर्चा के लिए आरआईएस ने भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) की साझेदारी में 28 अप्रैल 2017 को नई दिल्ली में 'उत्तरदायी अनुसंधान और नवाचार (आरआरआई); भारतीय परिप्रेक्ष्य पर राष्ट्रीय मंत्रणा' का आयोजन किया था।

प्रो. आशुतोष शर्मा, सचिव, डीएसटी, भारत सरकार, उद्घाटन भाषण देते हुए। (बाएं से दाएं): डॉ. के रवि श्रीनिवास, प्रो. सचिन चतुर्वेदी और डॉ. परवीन अरोड़ा।

उद्घाटन सत्र में आरआईएस के डॉ. के. रवि श्रीनिवास ने उपस्थित प्रतिभागियों का स्वागत किया। प्रो. सचिन चतुर्वेदी, महानिदेशक, आरआईएस, ने आरआरआई पर प्रस्तुति दी। डॉ. परवीन अरोड़ा, एससी–जी और प्रमुख–कॉर्ड डिवीजन, डीएसटी ने मुख्य भाषण दिया। प्रो. आशुतोष शर्मा, सचिव, डीएसटी, भारत सरकार, ने उद्घाटन भाषण दिया। आरआईएस के डॉ. अमित कुमार ने धन्यवाद ज्ञापन किया।

विस्तृत एजेंडा आरआईएस की वेबसाइट www.ris.org.in पर उपलब्ध है।

पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी

आरआईएस के भारतीय पारंपरिक चिकित्सा फोरम (एफआईटीएम) और आयुष मंत्रालय द्वारा 30 जून 2017 को नई दिल्ली में पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी (टीकेडीएल) पर एक हितधारक मंत्रणा आयोजित की गई। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय आईपीआर (एनआईपीआर) नीति 2016 में टीकेडीएल से संबंधित कार्य योजना (एक्शन प्वाइंट्स) पर हितधारकों के विचारों को जानना था।

उद्योग जगत, अनुसंधान संगठनों एवं विश्वविद्यालयों, मंत्रालयों तथा पेटेंट कार्यालय के प्रतिनिधित्व करने वाले एवं देश के विभिन्न हिस्सों से आए हितधारकों, पारंपरिक चिकित्सकों और पारंपरिक ज्ञान के विशेषज्ञों ने इस बैठक में भाग लिया। यह घरेलू स्तर पर और वैश्विक व्यापार व्यवस्था में भारतीय पारंपरिक चिकित्सा (आईटीएम) के प्रभाव एवं क्षमता का पता लगाने और अध्ययन करने के लिए एफआईटीएम के तहत आयोजित की गई पहली मंत्रणा थी जो आरआईएस और आयुष मंत्रालय द्वारा शुरू की गई।

(बाएं से दाएं): डॉ. मनोज नेसारी, सलाहकार (आयुष), आयुष मंत्रालय, प्रो. सचिन चतुर्वेदी, डॉ. राकेश तिवारी, प्रमुख, टीकेडीएल और प्रो. टी. सी. जेम्स।

इस मंत्रणा का शुभारंभ प्रो. सचिन चतुर्वेदी, महानिदेशक, आरआईएस, के स्वागत भाषण से हुआ। उद्घाटन भाषण डॉ. राजेश कोटेचा, विशेष सचिव, आयुष मंत्रालय की ओर से डॉ. मनोज नेसारी, सलाहकार (आयुष), आयुष मंत्रालय द्वारा दिया गया। प्रो. टी. सी. जेम्स, सदस्य सचिव, एफआईटीएम, ने मंत्रणा के दौरान हितधारकों द्वारा सुझाए जाने वाले मुद्दों के बारे में बताया। डॉ. राकेश तिवारी, प्रमुख, टीकेडीएल यूनिट, सीएसआईआर ने टीकेडीएल की वर्तमान स्थिति से प्रतिभागियों को अवगत कराया।

विस्तृत एजेंडा आरआईएस की वेबसाइट www.ris.org.in पर उपलब्ध है।

उत्तरदायी अनुसंधान और नवाचार

'पहुंच, बराबरी और समावेशन भारतीय संदर्भ में आरआरआई की कुंजी हैं '

–प्रो. आशुतोष शर्मा

प्रो. आशुतोष शर्मा

उत्तरदायी अनुसंधान और नवाचार (आरआरआई) के विषय को दो अहम स्तंभ हासिल हो गए हैं। पहला स्तंभ तो तकनीक है, और दूसरा स्तंभ समाज के साथ इसका सामाजिक–आर्थिक–राजनीतिक जुड़ाव (कनेक्ट) है। पूरे समाज के लाभ के लिए सार्थक तरीके से इस पारस्परिक जुड़ाव का लाभ कैसे उठाया जाए, यह एक बड़ा सवाल है। इस दिशा में जल्द ही उद्योग 4.0 के भी सक्रिय होने के आसार को देखते हुए इसकी विशेष अहमियत है। बिल्कुल ठीक इसी मायने में 'वैज्ञानिक सामाजिक दायित्व' का विचार (आइडिया) अत्यंत व्यावहारिक और सामयिक है, जिसकी वकालत खुद प्रधानमंत्री ने की है।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी (एसएंडटी) देश के सामाजिक–आर्थिक विकास की कुंजी है जो किसी भी वैज्ञानिक संस्थान की समाज के प्रति निश्चित जिम्मेदारी होती है। आरआरआई के रूप में नई रूपरेखा, जिस पर यूरोप के शैक्षणिक एवं नीतिगत हलकों में विशेषकर हाल के दिनों में विचार–विमर्श किया जा रहा है, विज्ञान–प्रौद्योगिकी–समाज संबंधी अध्ययनों में उभर कर सामने आई है और इसके तहत आरआरआई कुंजी का एक सेट प्रस्तुत किया गया है। हालांकि, आरआरआई की उन छह कुंजी या आधारों (अर्थात नैतिकता, सामाजिक भागीदारी, महिला–पुरुष समानता, खुली पहुंच, विज्ञान की शिक्षा और गवर्नेंस) के विशेष भारतीय मायने होना जरूरी है, जो कि यूरोपीय आयोग द्वारा प्रस्तावित हैं।

भारत जैसे देशों में समाज की बुनियादी जरूरतों जैसे कि सुरक्षित पेयजल, स्वास्थ्य की देखभाल, साफ–सफाई, स्वच्छ माहौल इत्यादि से संबंधित कई चुनौतियां हैं। विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार (एसटीआई) के फल उन व्यक्तियों, विशेषकर समाज के निचले सामाजिक–आर्थिक तपकों के उन लोगों तक नहीं पहुंच पाए हैं जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। अतः इन बुनियादी चुनौतियों से निपटने का अभिनव समाधान पेश करने वाली किसी भी तकनीकी उपलब्धि को पहुंच, बराबरी और समावेशन से जुड़े मुद्दों का भी हल अवश्य निकालना चाहिए। इसके मद्देनजर पहुंच, बराबरी और समावेशन (एईआई) की रूपरेखा भारतीय संदर्भ में आरआरआई को समझाने के लिहाज से अत्यंत उपयुक्त है।

समावेशन शब्द अपने व्यापक अर्थ में महिला–पुरुष समावेशन, भौगोलिक समावेशन और शैक्षणिक समावेशन तीनों को ही समाहित करता है। यह समावेशन ग्रामीणों, किसानों, युवाओं, छात्रों और दिव्यांगों को भी अपने दायरे में लाता है। डीएसटी ने समावेशन को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण पहले की हैं। भारत में एसएंडटी संबंधी अनुसंधान में महिला–पुरुष समानता को बढ़ावा देने के लिए डीएसटी ने 'किरण' नामक एक कार्यक्रम शुरू किया है, जिससे महिला वैज्ञानिकों को अपने कैरियर को नई दिशा देने और इसे पुनः शुरू करने में मदद मिलेगी।

विज्ञान संचार विशेष अहमियत रखता है और इस क्षेत्र में 'विज्ञान प्रसार' लोगों तक पहुंच (आउटरीच) बढ़ाने संबंधी विभिन्न गतिविधियों के जरिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है। ऐसा ही एक सफल प्रयास 'विज्ञान एक्सप्रेस' है, जो वैज्ञानिक विचारों का प्रचार–प्रसार करने और देश भर में विशाल आबादी के बीच वैज्ञानिक सोच को प्रोत्साहित करने के लिए देश के दूरदराज के कोनों तक सफर पर जाती है।

अनेक सामाजिक चुनौतियों के समाधान में प्रौद्योगिकी की अहम भूमिका की व्यापक संभावनाओं को देखते हुए यह भी ध्यान में रखा जाना चाहिए कि प्रौद्योगिकी हमें 'समर्थ' भी बना सकती है और 'दूसरों से अलग' भी बना सकती है। यह सामाजिक–राजनीतिक पहलू एक प्रमुख नीतिगत चुनौती है, जिसे भली–भांति ध्यान में रखना आवश्यक है। भविष्य के बारे में चर्चा करते वक्त हमें नैतिकता के साथ–साथ सामाजिक भागीदारी, बराबरी, गवर्नेंस इत्यादि से जुड़े मुद्दों पर भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। ये सभी तकनीकों पर निर्भर हैं। चूंकि प्रौद्योगिकी परिदृश्य व्यापक डेटा विश्लेषण और पूरी दुनिया से जुड़ी बुद्धिमान मशीनों के अभ्युदय के कारण बड़ी तेजी से बदल रहा है, इसलिए निर्णय लेना अब अधिक जटिल हो गया है जिसे मानव मन के लिए संभालना आसान नहीं है। ऐसे में नैतिकता के क्षितिज का विस्तार करने की जरूरत है।

पृष्ठ 10 पर जारी.....

पृष्ठ 9 से जारी.....

इसके साथ ही गवर्नेंस की नए मॉडल भी विकसित हो रहे हैं और ये सभी निकट भविष्य में ही संभव हो सकते हैं। यह सिलसिला निरंतर जारी रहेगा। यह अकेले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) की विलक्षणता के बारे में नहीं है, जो हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। हालांकि, हम प्रौद्योगिकी, मशीनों और भावी समाज के पारस्पारिक प्रभाव को जिस तरह से देखते हैं उसमें हमें निरंतर बदलाव नजर आएंगे।

इस परिदृश्य में विज्ञान नीति की अहम भूमिका इसे उपयुक्तं स्वरूप में प्रदान करने में है कि प्रौद्योगिकी को आखिरकार कैसे सार्वजनिक हित और सामाजिक कल्याण के लिए समाज के साथ संवाद सुनिश्चित करें, क्योंकि इसका वास्ता आदर्श बदलाव से है। प्रासंगिक वास्तविकताओं और आवश्यकताओं पर आधारित एक नई रूपरेखा पर विचार–विमर्श करने एवं विकसित करने की जरूरत है, ताकि प्रौद्योगिकी और समाज के बीच पारस्परिक जुड़ाव सुनिश्चित किया जा सके। इससे असंतोष के बजाय सद्भाव का माहौल बनेगा।

नई दिल्ली में 28 अप्रैल, 2017 को उत्तरदायी अनुसंधान और नवाचार पर आयोजित राष्ट्रीय मंत्रणा के दौरान भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग में सचिव प्रो. आशुतोष शर्मा द्वारा दिए गए उद्घाटन भाषण के अंश

राष्ट्रीय मंत्रणा ...
पृष्ठ 3 से जारी

एवं नीतिगत अनुसंधान संस्थान, डॉ. प्रेमा रामचंद्रन, भारतीय पोषण फाउंडेशन और श्री विशाल कुमार देव, आयुक्त–सह–सचिव, महिला एवं बाल विकास, ओडिशा सरकार शामिल थे।

श्री अमिताभ कांत, सीईओ, नीति आयोग, ने 'जलवायु परिवर्तन में कमी के लिए कृषि रणनीतियों के अनुकूलन' विषय पर सत्र–2 की अध्यक्षता की। सत्र की सह–अध्यक्षता श्री यदुवेन्दर माथुर, अपर सचिव, नीति आयोग, ने की। इस सत्र के पैनल सदस्यों में डॉ. सीएच. श्रीनिवास, निदेशक, केंद्रीय शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान संस्थान, श्री कृष्ण कुमार, डीडीजी, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय और डॉ. टी.पी. राजेंद्रन, विजिटिंग फेलो, आरआईएस, सभी शामिल थे।

'टिकाऊ कृषि और किसानों की आय दोगुनी करने' विषय पर सत्र–3 की अध्यक्षता प्रो. रमेश चन्द, सदस्य, नीति आयोग ने की। इस सत्र के मुख्य' पैनल सदस्यों में डॉ. एच. के. भानवाला, चेयरमैन, नाबार्ड, श्री के.के. मित्तल, अपर मुख्य सचिव एवं कृषि उत्पादन आयुक्त, असम सरकार और डॉ. राका सक्सेना, वरिष्ठ वैज्ञानिक, राष्ट्रीय कृषि अर्थशास्त्र एवं नीतिगत अनुसंधान संस्थान शामिल थे। समापन सत्र में 'भूख और कुपोषण पर वैश्विक परिप्रेक्ष्य'

श्री अमिताभ कांत, सीईओ, नीति आयोग 'एसडीजी 2 पर आयोजित राष्ट्रीय मंत्रणा में अपने विचार व्यक्त करते हुए।

विषय पर विशेष व्याख्यान भारत में एफएओ के प्रतिनिधि श्री श्याम खडका ने दिया। 'आगे के मार्ग' के सदर्भ में श्री जेन डेलबेरे, उप प्रतिनिधि, डब्लूएफपी और प्रो. सचिन चतुर्वेदी, डीजी, आरआईएस द्वारा संयुक्त रूप से जानकारी दी गई। समापन भाषण डॉ. पी. के. आनंद, वरिष्ठ सलाहकार, नीति आयोग द्वारा दिया गया।

दिन भर चली मंत्रणा के दौरान संबंधित विषय पर राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों, भारत सरकार की तात्कालिक प्राथमिकताओं एवं नीतिगत कार्यक्रमों, एसडीजी के संदर्भ में वैश्विक अनुभव एवं रुझान और नीति को लेकर सर्वोत्तम तौर–तरीकों और राज्यों की ओर से क्रियान्वयन पर व्यापक रूप से ध्यान केंद्रित किया गया। इन क्षेत्रों में विशिष्ट लक्ष्यों को प्राप्त करने में सिविल सोसायटी संगठनों की भूमिका पर भी चर्चा की गईं। गहन विचार–विमर्श वाले मुख्य मुद्दों में शामिल थे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, पीडीएस में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (नकद अंतरण), महिलाओं एवं बच्चों के बीच पोषण के नतीजे, जलवायु परिवर्तन एवं अनुकूलन रणनीतियों का प्रभाव, कृषि आय एवं ऋण, डेटा की गुणवत्ता, एसडीजी पर संकेतक का विकास और निगरानी।

आरआईएस–एक्जिम बैंक समर स्कूलः अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सिद्धांत और प्रथाएं

अंतरराष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में काम करने वाले विद्वानों के क्षमता निर्माण में योगदान करने के लिए आरआईएस ने भारत के एक्जिम बैंक के साथ मिलकर नई दिल्ली में 19–24 जून 2017 के दौरान अंतरराष्ट्रीय व्यापार में विशेषज्ञता वाले एम.फिल और पीएचडी छात्रों के लिए एक समर स्कूल का आयोजन किया। सुश्री रीता तेवतिया, वाणिज्य सचिव, वाणिज्य विभाग, वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार, ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया।

सुश्री रीता तेवतिया, वाणिज्य सचिव, वाणिज्य विभाग, वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार, ने आरआईएस–एक्जिम बैंक समर स्कूल का उद्घाटन किया।

पिछले कुछ वर्षों में आरआईएस ने बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली, क्षेत्रीय व्यापार व्यवस्थाओं, व्यापक आर्थिक सहयोग की संरचना, दक्षिण–दक्षिण सहयोग, व्यापार, प्रौद्योगिकी और निवेश के मुद्दों से जुड़ी अनुसंधान नितियों में अहम योगदान करने और संस्थान की मुख्य विशेषतायों को परिभाषित करने के लिए काफी ख्याति अर्जित की है जिससे अनगिनत शोध अध्ययनों और परिचर्चाओं का मार्ग प्रशस्त हुआ।

एक्जिम बैंक को भारत के अतंरराष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। भारत के अतंरराष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने, इसमें सहूलियत सुनिश्चित करने और वित्तपोषण करने के अलावा एक्जिम बैंक ऑफ इंडिया ने आर्थिक अनुसंधान अध्ययनों पर ध्यान केंद्रित करने हेतु विद्वानों को प्रोत्साहित करने के लिए एक नई पहल की हैं।

पाठ्यक्रम की संरचना में निम्नलिखित विषयों को शामिल किया गया; मॉड्यूल 1: व्यापार सिद्धांत में हालिया विकास मॉड्यूल 2: अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर डेटाबेस और सूचना, मॉड्यूल 3: व्यापार विश्लेषण में काम आने वाले साधन और तकनीक, मॉड्यूल 4: एफटीए और क्षेत्रीय व्यापार ब्लॉकों को समझना, मॉड्यूल 5: प्रौद्योगिकी में व्यापार के मुद्दे और वर्गीकरण से जुड़े मुद्दे, मॉड्यूल 6: व्यापार और विकास; आईपीआर एवं नए मुद्दे, और मॉड्यूल 7: समूह प्रस्तुतियां। देश भर के 35 से अधिक विद्वानों ने क्षमता निर्माण कार्यक्रम में भाग लिया।

वाणिज्य सचिव और आरआईएस संकाय–सदस्यों के साथ आरआईएस–एक्जिम बैंक समर स्कूल के प्रतिभागी।

पेसर प्लस और व्यापार एवं निवेश का भविष्य प्रशांत द्वीप की अर्थव्यवस्थाओं की संभावनाएं

प्रशांत द्वीप देशों (पीआईसी) के रूप में लोकप्रिय प्रशांत क्षेत्र के लघु द्वीप विकासशील देशों (एसआईडीएस) का स्थान उनकी अर्थव्यवस्था, आकार, संसाधन निधि, आबादी के आकार, जोखिमों एवं उनकी कमजोरी या भेद्यता के स्वरूप और भू–राजनीतिक संबंधों के आधार पर तय किया जाता है। पीआईसी विविध प्रकार के उपभोग के सामान के आयात, निवेश और विकास सहायता के लिए इस क्षेत्र की दो बड़ी एवं विकसित अर्थव्यवस्थाओं जैसे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड पर निर्भर रहते हैं।

एकतरफा व्यापार और निवेश नीतियों के अलावा पीआईसी कुछ मौजूदा व्यापार समझौतों के पक्षकार हैं। घनिष्ठ आर्थिक संबंधों पर प्रशांत समझौता (पेसर प्लस) दरअसल ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और 12 पीआईसी के बीच एक नया व्यापार एवं आर्थिक एकीकरण समझौता है। पेसर प्लस पर विभिन्न हितधारकों की ओर से मिश्रित प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है। इस समझौते के कुछ प्रावधानों को लेकर कुछ पीआईसी में असंतोष बढ़ रहा है। पीआईसी क्षेत्र के कुछ राष्ट्रीय संस्थानों के सहयोग से आरआईएस ने पीआईसी के लिए पेसर प्लस के फायदों और इस वजह से चुकाई जाने वाली कीमत पर बारीकी से गौर करने के लिए अध्ययन करने और उन्हें सागर–आश्रित अर्थव्यवस्थाओं के आर्थिक विकास एवं उन्नति की प्रक्रियाओं से जोड़ने का लक्ष्य तय किया है।

अधिक जानकारी के लिए कृपया इनसे संपर्क करें; डॉ. प्रियदर्शी दास: pdash@ris.org.in

एफआईडीसी पूर्वोत्तर क्षेत्रीय मंत्रणाएं

भारतीय विकास सहयोग नीति से संबंधित मुद्दों और पूर्वोत्तर में विकास के बारे में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास (डोनर) मंत्रालय के विजन पर विभिन्न हितधारकों के बीच संवाद सुनिश्चित करने के उद्देश्य से क्षेत्रीय मंत्रणाओं की एक श्रृंखला आयोजित करने की योजना बनाई जा रही है। इस मंत्रणा श्रृंखला के आयोजन का उद्देश्य पूर्वोत्तर राज्यों की विकास प्रक्रिया के दायरे में रहते हुए एवं उससे परे प्रगति की गुंजाइश, उद्देश्यों और तौर–तरीकों पर विचार–विमर्श करने का अवसर प्रदान करना है। इसके तहत इरादा राष्ट्रीय सीमा से परे जनसंपर्क को बढ़ावा देने और एक्ट ईस्ट के नजरिए से क्षेत्रीय मूल्य श्रृंखला (वैल्यू चेन) बनाने के लिए एक प्रभावी केंद्र (हब) के रूप में पूर्वोत्तर राज्यों को स्थापित करने की संभावनाओं को तलाशना है।

पूर्वोत्तर क्षेत्रीय मंत्रणाओं के दौरान स्थानीय स्तर पर भागीदारी की भावना बढ़ाने हेतु प्रमुख भागीदारों की पहचान करने के लिए अथक प्रयास किए जाएंगे।

अधिक जानकारी के लिए कृपया इनसे संपर्क करें; प्रो. मिलिंदो चक्रबर्ती: milindo.chakrabarti@ris.org.in

भारतीय पारंपरिक चिकित्सा फोरम (एफआईटीएम)

आयुष मंत्रालय ने आरआईएस में भारतीय पारंपरिक चिकित्सा फोरम (एफआईटीएम) की स्थापना समस्त संगठनों एवं निकायों और हित धारकों के लिए एक आम या साझा प्लेटफॉर्म के रूप में की है जहां वे इस क्षेत्र में व्यावहारिक नीति के निर्माण में योगदान करने और एक ऐसी सक्रिय रणनीति विकसित करने के लिए एकजुट हो सकते हैं जिसकी हिमायत भारत अंतरराष्ट्रीय स्तर पर करेगा। एफआईटीएम विभिन्नि तरह के अध्ययन कराएगा, पारंपरिक चिकित्सा के क्षेत्र में अध्ययन के लिए फेलोशिप एवं छात्रवृत्ति देगा, राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों द्वारा अतिथि व्याख्यान आमंत्रित परिचर्चाओं की व्यवस्था करेगा, भारत में विभिन्न स्थानों पर हितधारकों के साथ समय–समय पर मंत्रणाएं आयोजित करेगा और सरकार को नीतिगत सलाह प्रदान की जाएगी अधिक जानकारी के लिए कृपया इनसे संपर्क करें; प्रो. टी. सी. जेम्स: tcjames@ris.org.in

क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता; एक रणनीति की आवश्यकता है

क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (आरसीईपी) समझौते के सदस्य देश दुनिया की आधी आबादी, वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 30 प्रतिशत और विश्व व्यापार के एक चौथाई हिस्से को कवर करते हैं। इस क्षेत्रीय समूह में चीन सहित कई देश हैं जिनकी अर्थव्यवस्थाएं दुनिया के सर्वाधिक निर्यात प्रतिस्पर्धी देशों में शामिल की जाती हैं। संबंधित वार्ताएं भारत के लिए अत्यंत चुनौतीपूर्ण साबित होंगी। इस क्षेत्र के देशों के साथ भारत के पूर्ववर्ती एफटीए या सीईएपी अपने कार्यान्वयन में सफलता के मॉडल साबित नहीं हुए हैं, भले ही उनसे लाभ हुए हों। यदि आरसीईपी को इनसे भी कहीं अधिक सफल साबित होना है, तो खूब सोच–समझ कर योजनाएं एवं रणनीतियां बनानी होंगी। भारत को हासिल होने वाली रियायतों के मद्देनजर और अधिक प्रतिस्पर्धी बनना पड़ेगा, जिससे कि इन्हें अपेक्षित बाजार पहुंच में तब्दील किया जा सके। भारत को पर्याप्त लचीलापन भी हासिल करना चाहिए, ताकि घरेलू खिलाड़ियों अथवा कारोबारियों को प्रतिस्पर्धाओं का सामना करने में सक्षम होने के लिए समान अवसर अवश्य ही मिल सकें। इस पेपर (पत्र) में एक संभावित दृष्टिकोण और रणनीति का खाका पेश किया गया है।

माननीया विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज आसियान–भारत साझेदारी के 25 वर्ष पर आयोजित कार्यक्रम के अवसर पर अन्य गणमान्य व्यक्तियों के साथ।

अन्य मंचों पर नीतिगत संवाद

प्रो. सचिन चतुर्वेदी

महानिदेशक

- नई दिल्ली में 6 अप्रैल 2017 को भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) और विदेश मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित भारत–अफ्रीका स्वास्थ्य विज्ञान सहयोग – कार्यदल की बैठक में भाग लिया।
- 7 अप्रैल 2017 को नई दिल्ली में आईसीडब्ल्यूए–चीन सूंग चिंग लिंग फाउंडेशन (सीएससीएलएफ) संवाद में भारत–चीन संबंध में मीडिया की भूमिका पर सत्र की अध्यक्षता की एवं आर्थिक संबंध के विकास के संदर्भ में कनेक्टिविटी पर एक प्रस्तुति दी।
- 17 अप्रैल 2017 को काठमांडू में रणनीतिक एवं सामाजिक आर्थिक अनुसंधान संस्थान (आईएसएसआर), संयुक्त राष्ट्र एस्कैप, द एशिया फाउंडेशन और पैवेलियन ग्रुप द्वारा संयुक्त रूप से 'बीबीआईएन देशों के बीच सहयोग बढ़ाना; आगे की राह' पर आयोजित सम्मेलन में मुख्य भाषण दिया।
- 22–23 अप्रैल 2017 को ढाका में बांग्लादेश सरकार और नीतिगत संवाद केंद्र (सीपीडी), ढाका द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित बिम्सटेक नेटवर्क ऑफ पॉलिसी थिंक टैंक्स (बीएनपीटीटी) की तीसरी बैठक में भाग लिया।
- 12 मई 2017 को नई दिल्ली में टीएएएस, आईएफपीआरआई और आईसीएआर द्वारा संयुक्त रूप से 'सतत विकास लक्ष्य ; भारत की तैयारियां और कृषि की भूमिका' पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में 'एसडीजी की प्रप्ति के लिए रणनीतियां' विषय पर आयोजित सत्र में पैनलिस्ट थे।
- 12 मई 2017 को नई दिल्ली में भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएसएसआर) के स्थापना दिवस कार्यक्रम में ' अनुसंधान और अंतर्राष्ट्रीय प्रभावशीलता; कैसे भारतीय क्षमताओं से लाभ उठाएं' विषय पर विशेष भाषण दिया।
- 28 मई 2017 को बर्लिन में नेस्ट वैश्विक कार्यकारिणी बैठक में भाग लिया।
- 28 मई 2017 को बर्लिन में जर्मन विकास संस्थान (जीडीआई) द्वारा 'जीपीईडीसी का भविष्य' पर आयोजित अनौपचारिक आदान–प्रदान में भाग लिया।
- 29 मई 2017 को बर्लिन में जर्मन विकास संस्थान (जीडीआई) द्वारा जर्मन प्रेसीडेंसी के तहत आयोजित उच्चस्तरीय टी 20 शिखर सम्मेलन में भाग लिया।
- 30 मई 2017 को ओस्लो में शांति अनुसंधान संस्थान ओस्लो (पीआरआईओ) और रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान (आईडीएसए) द्वारा संयुक्त रूप से 'भारत की खाद्य सुरक्षा; स्थानीय और वैश्विक आयाम' पर आयोजित संयुक्त कार्यशाला में 'बहुपक्षीय वार्ताओं में भारत की खाद्य सुरक्षा चिंताओं ' पर एक प्रस्तुति दी।
- 5 जून 2017 को नई दिल्ली में भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य फाउंडेशन (पीएचएफआई), पर्यावरण स्वास्थ्य केंद्र और टीआईएसएस द्वारा संयुक्त रूप से पर्यावरण स्वास्थ्य पर आयोजित राष्ट्रीय मंत्रणा में 'सतत विकास लक्ष्यों के संदर्भ में स्वास्थ्य और पर्यावरण' विषय पर एक प्रस्तुति दी।
- 9 जून 2017 को चीन के फूजौ में आयोजित ब्रिक्स सिविल सोसायटी संगठन (सीएसओ) फोरम की बैठक में भाग लिया।
- 10–13 जून 2017 को चीन के फूजौ में आयोजित नौवें ब्रिक्स शैक्षणिक फोरम में 'ब्रिक्स सहयोग व्यवस्था को और आगे बढ़ाने के विचार एवं सुझाव' पर एक प्रस्तुति दी।
- 12–13 जून 2017 को बर्लिन में वित्त के लिए जर्मन संघीय मंत्रालय, आर्थिक सहयोग एवं विकास के लिए जर्मन संघीय मंत्रालय और ड्यूश बंडेसबैंक द्वारा संयुक्त रूप से 'जी20 अफ्रीका साझेदारी – साझा भविष्य में निवेश करने' विषय पर आयोजित अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लिया।
- 15 जून 2017 को मास्को में राजनयिक अकादमी, रूस के विदेश मंत्रालय द्वारा रूस और भारत के बीच राजनयिक संबंधों की शुरुआत की 70वीं वर्षगांठ पर आयोजित गोलमेज परिचर्चा में 'भारत–रूस आर्थिक सहयोग' पर एक प्रस्तुति दी।
- 21 जून 2017 को नई दिल्ली में मैकैंजी एंड कंपनी, ओआरएफ और टीटीसीएसपी द्वारा संयुक्त रूप से 'नए चेहरे और नई रणनीतियां; थिंक टैंक्स के लिए एचआर और फंडिंग चुनौतियां' विषय पर आयोजित गोलमेज परिचर्चा में भाग लिया।
- 27 जून 2017 को भोपाल में पंचायती राज मंत्रालय द्वारा आयोजित राज्यों के पंचायती मंत्रियों के सम्मेलन में 'एसडीजी के साथ नए भारत के लिए स्मार्ट पंचायतों' पर एक प्रस्तुति दी।
- 30 जून 2017 को नई दिल्ली में राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज (एनडीसी) द्वारा आयोजित 57 वें एनडीसी कोर्स में 'वैश्वीकरण, क्षेत्रीय व्यापार गठबंधन और डब्ल्यूटीओ' पर एक प्रस्तुति दी।

प्रो. एस. के. मोहंती

- 13 अप्रैल 2017 को नई दिल्ली में फिक्की द्वारा अमेरिकी राष्ट्रीय नीति पर आयोजित परिचर्चा बैठक में भाग लिया।
- 15 मई 2017 को नई दिल्ली में वाणिज्य मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में 'भारत–मॉरीशस सीईपीए वार्ताओं' पर आयोजित परिचर्चा बैठक में भाग लिया।
- 16 जून 2017 को वाणिज्य विभाग, नई दिल्ली में आयोजित परिचर्चा बैठक में भाग लिया और परियोजना अध्ययन 'व्यापार और निवेश में एलएसी देशों के साथ भारत की साझेदारी' पर एक प्रस्तुति दी।

प्रो. टी. सी. जेम्स

विजिटिंग फेलो

- 23 मार्च 2017 को नई दिल्ली, में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, दिल्ली द्वारा कॉरपोरेट कानूनों पर आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय सममेलन में भाग लिया और बौद्धिक संपदा कानूनों पर आयोजित सत्र की अध्यक्षता की।
- 7 अप्रैल 2017 को भारतीय कानून संस्थान, नई दिल्ली, द्वारा बौद्धिक संपदा अधिकारों और सार्वजनिक हित पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में संसाधन व्यक्ति के रूप में भाग लिया और विशेष भाषण दिया।
- 8–9 अप्रैल 2017 को आईपीआर पर डीआईपीपी चेयर और नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, जोधपुर, द्वारा कॉपीराइट एवं प्रौद्योगिकी पर आयोजित सम्मेलन में भाग लिया और ज्ञान एवं सूचना तक पहुंच पर भाषण दिया।
- नई दिल्ली में 20 अप्रैल 2017 को दिल्ली विश्वविद्यालय, कैम्पस लॉ सेंटर द्वारा 'मनोरंजन उद्योग में पायरेसी' पर आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला में सम्मानित अतिथि के रूप में भाग लिया।
- 27 अप्रैल 2017 को नई दिल्ली में शैक्षणिक संस्थानों के विशेष संदर्भ के साथ कॉपीराइट कानून पर कैम्पस लॉ सेंटर में आयोजित गोलमेज परिचर्चा में विशिष्ट पैनलिस्ट के रूप में भाषण दिया।
- 19 मई 2017 को नई दिल्ली में दिल्ली न्यायिक अकादमी में दिल्ली न्यायिक सेवा अधिकारियों के लिए बौद्धिक संपदा अधिकारों की कानूनी अवधारणाओं और आईपीआर एवं प्रवर्तन पर उन्मुखीकरण कार्यक्रम में ट्रायल और प्रक्रिया के मुद्दों पर भाषण दिया।
- 30 मई 2017 को हिमाचल प्रदेश सरकार, एनएफआई और हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान (एचआईपीए) द्वारा संयुक्त रूप से नोडल अधिकारियों के लिए एसडीजी पर आयोजित उन्मुखीकरण कार्यक्रम में संसाधन व्यक्ति के रूप में भाग लिया और एचआईपीए, ढाली, शिमला, हिमाचल प्रदेश में 'भारत में एसडीजी ; केंद्र से लेकर राज्य स्तर तक ' विषय पर भाषण दिया।

डॉ. के. रवि श्रीनिवास

विजिटिंग फेलो

- 15–16 मई 2017 को वियना में आयोजित न्यू हॉरिजन परियोजना की शुरुआती बैठक में भाग लिया।

डॉ. प्रियदर्शी दास

रिसर्च एसोसिएट

- 8–10 मई 2017 के दौरान जकार्ता में आयोजित द्वितीय आईओआरए नीली अर्थव्यवस्था मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में आरआईएस का प्रतिनिधित्व किया।
- 25–26 मई 2017 को सुवा, फिजी में आयोजित भारत–प्रशांत द्वीप समूह सतत विकास सम्मेलन में नीली अर्थव्यवस्थाओं पर पूर्ण और विषयगत सत्रों में पैनलिस्ट के रूप में एक प्रस्तुति दी।
- 22–26 जून 2017 के दौरान बीजिंग, चीन, में आयोजित भारत–चीन थिंक टैंक फोरम की बैठक में भाग लिया और 'भारत एवं चीन के बीच विनिर्माण क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग' विषय पर व्याख्यान दिया।

डॉ. सब्यसाची साहा

सहायक प्रोफेसर

- 28–30 मार्च के दौरान यूएनडीपी और कोटे डी आइवर की सरकार द्वारा अबिदजान में 'अफ्रीका के उद्भव (आईसीईए)' पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में 'उद्भव, बदलाव और समावेशन के लिए डिजिटल इकोनॉमी; भारत में हालिया प्रगति' पर एक प्रस्तुति दी।
- 16 मई 2017 को गुआंगजौ, चीन, में 'ब्रिक्स सहयोग और वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं' पर आयोजित 2017 ब्रिक्स थिंक टैंक संगोष्ठी में 'उच्च प्रौद्योगिकी में इंट्रा–ब्रिक्स व्यापार; ब्रिक्स में औद्योगिक मूल्य श्रृंखलाओं के अवसर' पर एक प्रस्तुति दी।

नवीनतम प्रकाशन

रिपोर्ट

एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर; सतत और अभिनव विकास के लिए साझेदारी; एक विजन दस्तावेज

आरआईएस, ईआरआईए, आईडीई–जेट्रो, नई दिल्ली, 2017

मेकांग–गंगा सहयोग; बाधाएं समाप्त करना और नए मुकाम की तलाश करना

एआईसी – आरआईएस, नई दिल्ली, 2017

आरआईएस परिचर्चा पत्र

#209 क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता; एक रणनीति की आवश्यकता है, वी.एस.शेषाद्री

आरआईएस नीतिगत सारपत्र

#78 भारत और अन्य ब्रिक्स देशों में विनिर्माण; लड़खड़ाता प्रदर्शन, मनमोहन अग्रवाल, जून 2017

पत्र- पत्रिकाएं

एशियाई जैव प्रौद्योगिकी और विकास की समीक्षा

खंड 19 संख्या 1 मार्च 2017

साउथ एशिया इकोनॉमिक जर्नल

खंड 18 संख्या 1 अप्रैल 2017

आरआईएस डायरी

खंड 13 संख्या 2 अप्रैल 2017

ब्लू इकोनॉमी नीतिगत सारपत्र

#2 ब्लू इकोनमी, महासागर विकास और एसडीजी–14: समुद्री परितंत्र के लिए निहितार्थ द्वारा एस. के. मोहंती और पंखुड़ी गौड़, आरआईएस, अप्रैल 2017, नई दिल्ली

आरआईएस संकाय द्वारा बाह्य प्रकाशनों में योगदान

चतुर्वेदी, सचिन. 2017. 'भारत की बढ़ती आर्थिक ताकत और वैश्विक भूमिका; विकास एवं गरीबी का आपसी नाता और अमेरिकी नीति के लिए प्रासंगिकता।' भारत का अभ्युदय और विकास चुनौतियां; अमेरिका के लिए नीतिगत निहितार्थ पर एस्पेन इंस्टीट्यूट कांग्रेसनल प्रोग्राम 18–26 फरवरी 2017 को, नई दिल्ली और हैदराबाद, खंड 33 संख्या 1 ।

चतुर्वेदी, सचिन और कृष्ण रवि श्रीनिवास. 2017. 'बौद्धिक संपदा अधिकार, नवाचार और भारत के लिए चावल रणनीति', द फ्यूचर राइस स्ट्रेटेजी फॉर इंडिया द्वारा पी. चेंगप्पा, एम. हेगडे और एस. मोहंती (ईडीएस) . एल्सेवियर; आईआरआरआई . पेज 277–299।

चतुर्वेदी, सचिन. 2017. 'मोदी जर्मनी में; क्या भारत की एफटीए व्यावहारिकता ईयू को उसके ढांचे से बाहर ले आएगी ?', *बिजनेस स्टैंडर्ड*, 29 मई।

चतुर्वेदी, सचिन . 2017. 'गलियारों से परे कैसे पहुंचें' *द इकोनॉमिक टाइम्स* , 14 जून, नई दिल्ली।

डे, प्रबीर. 2017. 'लुक ईस्ट से लेकर एक्ट ईस्ट तक ; आसियान के साथ भारत की आर्थिक सहभागिता' सी. जे. थॉमस और के. सारदा (संपादक) *एक्ट ईस्ट और भारत का पूर्वोत्तर क्षेत्र*, पेंटागन प्रेस, नई दिल्ली।

डे, प्रबीर. 2017. 'आसियान–भारत संबंध की समकालीन रूपरेखा'. वर्ल्ड ट्रेड सेंटर (संपादित) पुस्तिका ; इंटरनेशनल ट्रेड, मुम्बई।

डे, प्रबीर. 2017. 'दक्षिण एशियाई देश बना रहे हैं कनेक्शन'. *ईस्ट एशिया फोरम*, 24 जून 2017।

डे, प्रबीर. 2017. 'बीबीआईएन ; पारगमन से लेकर आर्थिक कॉरिडोर तक'. *ट्रेड इनसाइट*, खंड 12 संख्या 3।

मोहंती, एस.के. 2017. ब्लू इकोनॉमी विजन 2025: भारत के कॉरपोरेट जगत और अंतरराष्ट्रीय भागीदारों के लिए कारोबारी संभावनाओं का दोहन करने' पर पेश किए गए ज्ञान पेपर में एक अध्याय का योगदान दिया. फिक्की कार्यदल द्वारा प्रकाशित, अप्रैल।

मोहंती, एस.के., प्रियदर्शी दास, सानुरा फर्नांडीज और पंखुड़ी गौड़ . 2017. भारत–मॉरीशस संयुक्त अध्ययन समूह की मसौदा रिपोर्ट. वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, चर्चा के लिए, जून।

RIS
Research and Information System for Developing Countries
विकासशील देशों की अनुसंधान एवं सूचना प्रणाली

कोर 4-बी, चौथा तल, भारत पर्यावास केन्द्र, लोधी रोड, नई दिल्ली-110 003, भारत । दूरभाष: 91-11-24682177-80
फैक्स: 91-11-24682173-74, ई-मेल: dgoffice@ris.org.in
वेबसाइट: http://www.ris.org.in

Follow us on:
www.facebook.com/risindia @RIS_NewDelhi www.youtube.com/RISNewDelhi

प्रबंध संपादक: तीश मल्होत्रा

प्रो. सुखमय चक्रवर्ती का विकास और भारतीय नीति में अहम योगदान

प्रो. मनमोहन अग्रवाल

प्रो. चक्रवर्ती विविध विषयों का अपार ज्ञान रखने वाले प्रकांड विद्वान थे। एक अर्थशास्त्री होने के बावजूद वह विविध गतिविधियों से सक्रियतापूर्वक जुड़े रहते थे। वह एक कुशल शिक्षक, एक नीति–निर्माता एवं एक विकास अर्थशास्त्री थे। उन्होंने विकास सिद्धांत पर नई एकीकृत आम सहमति सुनिश्चित करने के लिए पूरी सक्रियता के साथ अथक प्रयास किए। उन्होंने अनुसंधान एजेंडे के विकास में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। वह आरआईएस सहित ऐसे अनेक निकायों के प्रमुख रहे जिन्होंने आर्थिक अनुसंधान को निरंतर नई गति प्रदान की। वह आरआईएस की स्थापना के समय से ही इससे जुड़े रहे। अपने वैश्विक दृष्टिकोण के अनुरूप वह इस अहम अनुसंधान पर सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता पर विश्वास करते थे कि अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली आखिरकार किस तरह से विकासशील देशों की जरूरतों के साथ तारतम्यता बनाए रख सकती है। यह अनुसंधान ही दक्षिण–दक्षिण सहयोग की नींव रखेगा।

उन्होंने विद्वत्ता और लोकतांत्रिक बहस पर सदैव विशेष जोर दिया। वह उन रूढिवादी अर्थशास्त्रियों और नीति निर्माताओं से बिल्कुल भिन्न थे जो केवल विकास दर में दिलचस्पी रखते थे। विकास के विभिन्न मॉडलों से खुद को पूरी तरह अवगत रखने और इस क्षेत्र में स्वयं का अच्छा–खासा योगदान रहने के बावजूद भी उनका नजरिया बिल्कुल अलग था।

उन्होने इन श्रेणियों में व्यापक अनुसंधान किए ; (1) विकास से जुड़े कई मुद्दों का गणितीय अन्वेषण (2) विकास अर्थशास्त्र का संकल्पनात्मक आधार, जिसके तहत इसके ऐतिहासिक और बौद्धिक उद्‌गम दोनों पर ही विशेष जोर दिया जाता है (3) भारत में विकास, विशेषकर नियोजन से जुड़े मुद्दे और (4) विकास के मौद्रिक एवं वित्तीय पहलू जिससे विकास अर्थशास्त्र में वास्तविक और वित्तीय मुद्दों का एकीकरण संभव हो पाता है।

प्रो. चक्रवर्ती के अनुभव ने अपेक्षाकृत अधिक अवधि तक नीति निर्माण में निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए राजनीतिक आम सहमति के महत्व को दर्शाया। पचास एवं साठ के दशकों में विकास नीति पर आम सहमति रही, जिसका उदाहरण संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञ समूह की रिपोर्ट 1951 में दिया गया है। यह आम सहमति 25 से भी अधिक वर्षों तक बरकरार रही और फिर अंततः अस्सी के दशक में नदारद हो गई, जिसके लिए यह दलील दी गई कि विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के आय स्तर में भारी अंतर होने के बावजूद समान अर्थशास्त्र इन दोनों ही तरह के देशों पर लागू किया जाता रहा है।

विकास सुनिश्चित करने के लिए कृषि उत्पादकता में बढ़ोतरी निहायत ही जरूरी है। केवल तभी अधिशेष या सरप्लस कामगारों को उद्योग जगत में स्थानांतरित किया जा सकता है। हालांकि, तेजी से विकास सुनिश्चित करने के लिए पूंजीगत सामान का उत्पादन आवश्यक था। इसके साथ शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण का भी प्रसार होने की स्थिति में त्वरित विकास के साथ–साथ औद्योगिक क्षेत्र में मौजूद व्यापक उत्पादन स्तर का दोहन करने का भी मार्ग प्रशस्त होगा।

कृषि विकास से जुड़ी उनकी पसंदीदा नीति का उद्देश्य छोटे खेतों की उत्पादकता में बढ़ोतरी करना था। हालांकि, इसके लिए भौतिक कारक संबंधी निधि के समुचित आकलन, उत्पादन तकनीकों की जानकारी और संपत्ति के अधिकारों पर आधारित व्यापक असर वाले सुधारों को लागू करने की आवश्यकता है। उनके अनुसार, छोटी जोत के धारकों पर आधारित विकास पथ पर चलने से गरीब परिवारों की पसंदीदा फसलों का उत्पादन सुनिश्चित होगा और छोटी जोत में उपलब्ध संभावित अधिशेष (सरप्लस) को हासिल करने में मदद मिलेगी। आखिरकार यह वही विकास रणनीति थी जिस पर विकास संबंधी पूर्ववर्ती लेखों में विशेष बल दिया गया था। इन शुरुआती लेखों के अंतर्गत ग्रामीण रोजगार पैटर्न में जिन अंतर्निहित संभावनाओं पर विशेष बल दिया गया है उनका इस्तेमाल ग्रामीण रोजगार योजना के जरिए संपत्ति सृजन के लिए किया जा सकता है।

प्रो. चक्रवर्ती ने यह बात रेखांकित की थी कि भारत के प्रदर्शन में एक कमी तकनीकी क्षमताओं को विकसित करने में उसकी असमर्थता थी। भारतीय उद्योग में तकनीकी फर्क बढ़ा है। ज्ञान और पूंजीगत वस्तुओं के आयात की जरूरत महसूस की जा रही थी क्योंकि उनमें अत्यधिक तकनीकी प्रगति सन्निहित होती है। हालांकि, आयात के चलते घरेलू क्षमताओं में कमी नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा, एफडीआई पर निर्भरता से संभवत; सस्ते पूंजीगत सामान का मार्ग प्रशस्त नहीं होगा। दरअसल, यही वह तरीका है जिससे लाभकारी प्रभाव फैलता है। उनका यह मानना था कि विदेशी तकनीक हासिल करने का सबसे अच्छा तरीका जापानी तरीका है जिसके तहत पूंजी अर्थात एफडीआई की आपूर्ति से प्रौद्योगिकी के आयात को अलग करने में कामयाबी मिली।

इसके अतिरिक्त, मानव पूंजी में निवेश आवश्यक है, ताकि विदेशी प्रौद्योगिकी से जुड़ी समुचित जानकारी हासिल की जा सके। वैसे तो वह भारत में पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन के महत्व पर निरंतर विशेष जोर देते रहे, लेकिन फिर भी उन्होंने अधिशेष कामगारों वाली अर्थव्यवस्था के लिए निवेश के उचित पैटर्न के बारे में अपने विचारों को बदल दिया। वह पहले पूंजीगत सामान पर विशेष जोर देते थे, लेकिन बाद में वह निवेश पर विशेष बल देने लगे थे। चूँकि इससे कृषि क्षेत्र में बदलाव आएगा और गरीबों द्वारा उपभोग की जाने वाली वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि भी होगी।

प्रो. चक्रवर्ती ने यह बात रेखांकित की कि कृषि क्षेत्र में संक्रमण या परिवर्तन के दौर को पूरा करना, नई तकनीक को आत्मसात करने के लिए क्षमता बढ़ाना और स्वास्थ्य एवं शिक्षा सुविधाओं को बेहतर करना सरकार की मुख्य जिम्मेदारियां हैं। दरअसल, अपने समाज को और अधिक मानवीय अथवा दयापूर्ण बनाने के लिए ये सभी बदलाव अत्यंत आवश्यक हैं।

प्रो. सुखमय चक्रवर्ती द्वारा 'विकास और भारतीय नीति ' में दिए गए अहम योगदान पर विशेष व्याख्यान के अंश, जो प्रो. मनमोहन अग्रवाल द्वारा नई दिल्ली में 17 मार्च 2017 को आरआईएस में दिया गया था।